भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2429
(जिसका उत्तर सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/ 27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

अमेरिकी डॉलर के प्रति भारतीय रुपए का मूल्य

2429. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 30 मई, 2014 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य 59.18 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर था जो 24 नवंबर, 2023 को घटकर 83.34 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट का विदेशों के साथ व्यापार विशेष रूप से चीन, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, मध्य पूर्व के देशों, यूरोपीय संघ आदि से भारी मात्रा में आयात पर भारी प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट को नियंत्रित करने और व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान आयात के लिए अमेरिकी डॉलर के रूप में कितना व्यय किया गया और तदनुरूपी वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) 30 मई, 2014 और 24 नवंबर, 2023 को अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1: अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर

दिनांक	यूएसडी की तुलना में आईएनआर की विनिमय दर
30 मई, 2014	59.03
24 मई, 2023	83.37

नोट: आंकड़े दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है।
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक / एफबीआईएल संदर्भ दरें

भारतीय रुपये का मूल्य बाजार-निर्धारित है। भू-राजनीतिक तनाव, दुनिया भर में आक्रामक मौद्रिक नीति की सख्ती और कच्चे तेल की कीमतों में हालिया उछाल कुछ ऐसे कारक हैं जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये पर दबाव डाल रहे हैं।

(ख) किसी मुद्रा के अवमूल्यन से उसके निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि माल का आयात महंगा हो जाता है। हालांकि, विनिमय दर केवल कई कारकों में से एक है जो अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात की मांग को प्रभावित करती है। इन कारकों में व्यापार योग्य वस्तुओं की किस्म (अर्थात आवश्यक या लक्जरी वस्तुएं), विकल्प की उपलब्धता, माल ढुलाई लागत, निर्यात की मांग करने वाले देशों की आय में वृद्धि आदि शामिल हैं। इस प्रकार, निर्यात और आयात के स्तरों पर अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के हाल के अवमूल्यन के प्रभाव को अलग-थलग नहीं किया जा सकता है।

(ग) भारतीय रुपये (आईएनआर) की विनिमय दर बाजार-निर्धारित है, जिसके लिए लक्ष्य या विशिष्ट स्तर या बैंड नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अनुचित अस्थिरता से बचते हुए अपने व्यवस्थित कामकाज और विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है। आरबीआई ने हाल ही में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को कम करने और वैश्विक उछाल को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा वित्त पोषण के स्रोतों में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इनमें से कुछ उपाय हैं:

- वृद्धिशील विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] और अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमा देनदारियों को 4 नवंबर, 2022 तक एकत्रित जमा के लिए सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव से छूट दी गई थी।
- नवीन एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमाओं में 31 अक्टूबर, 2022 तक ब्याज दरों पर मौजूदा विनियमन से (ब्याज दरें समान घरेलू रुपया सावधि जमा पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं होंगी) छूट दी गई थी।
- भारतीय ऋण लिखतों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रवाह में एफपीआई निवेश से संबंधित विनियामक व्यवस्था को संशोधित किया गया है।

- विदेशी वाणिज्यिक उधार सीमा (स्वचालित मार्ग के तहत) को बढ़ाकर 1.5 अरब डॉलर कर दिया गया था और 31 दिसंबर, 2022 तक चुनिंदा मामलों में समग्र लागत (ऑल-इन-कॉस्ट) सीमा को 100 बीपीएस तक बढ़ा दिया गया था।
- एडी कैट-1 बैंक विदेशी मुद्रा उधार का उपयोग विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए कर सकते हैं ताकि वाणिज्यिक उधारों के संदर्भ में यथाप्रयोज्य उद्दीष्ट उपयोग किया जा सके।

इसके अलावा, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के बढ़ते एकीकरण को ध्यान में रखते हुए निर्यात को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। कुछ उपायों में निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करना, डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाओं को आसान बनाना और भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों और संगठनों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत करना शामिल है। विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात निष्पादन की नियमित निगरानी की जा रही है और समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा, नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल, 2023 से शुरू की गई है। नीति में भारत को वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करने और इसे एक विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यापार भागीदार बनाने के लिए एक ब्लू प्रिंट निर्धारित किया गया है। यह भारत के व्यापार निष्पादन और प्रतिस्पर्धा में और सुधार करेगा।

(घ) भारत के आयात भुगतान और विदेशी मुद्रा भंडार पर डेटा नीचे तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2: भारत का आयात और विदेशी मुद्रा भंडार

						(बिलियन अमेरिकी डॉलर)
क्र. सं.	**मदें**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1.	आयात भुगतान	517.5	477.9	398.5	618.6	721.4
2.	विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च के अंत)	412.9	477.8	577.0	607.3	578.4
3.	विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन	-11.7	64.9	99.2	30.3	-28.9

स्रोत: आरबीआई।

****